

गंगा भारतीयों की आस्था

संजय गोस्वामी,
अणुशक्तिनगर, मुंबई

गंगा भारतीयों की आस्था का आधार है। उसमें हम माँ का स्वरूप देखते हैं। गंगा हमें स्वर्ग के द्वार तक ले जाने वाली देवी है। इस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए लोग देश-विदेश से यहाँ आते हैं। धार्मिक और परम्परागत सामाजिक मेलों में प्रत्येक वर्ष गंगा के तट पर करोड़ों लोगों की उमड़ने वाली भीड़ और उसमें प्रदूषण के प्रति जानकारी व जागरूकता का अभाव ही गंगा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। वर्तमान में गंगा त्राहि-त्राहि कर रही है। भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, पवित्र और महिमामयी नदी गंगा उत्तरांचल में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में विद्यमान सुन्दरवन डेल्टा का अभिसिंचन करते हुए एक विशाल भू-भाग को हरा-भरा बनाती है। स्वर्गगंगा, त्रिपथगा, पातालगंगा, भागीरथी, जाह्नवी, मन्दाकिनी, अलकनन्दा आदि विभिन्न नामों से पुकारी जाने वाली यह गंगा नदी जन-जन की भावनात्मक आस्था का आधार है। वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में गंगा का विषद वर्णन मिलता है। वस्तुतः गंगा नदी हरिद्वार से लगभग 300 कि.मी. दूरी पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। मैदानी यात्रा करते हुए गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुँचती है। यहाँ इसका संगम यमुना के साथ होता है। यह संगम स्थल हिन्दुओं का एक पवित्र तीर्थ है जिसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। लेकिन गंगा के तट पर घनी आबादी वाले औद्योगिक नगरों के अपशिष्ट के सीधे गंगा नदी में गिरने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई वर्षों से एक समस्या के रूप में हमारे सामने है। अब समय है पवित्र गंगा को बचाने की। पहली बार गंगा को निर्मल और अविरल बनाने पर गंभीर पहल होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा की सफाई को राष्ट्रीय महत्त्व का दर्जा देकर जन आन्दोलन बनाने का भरोसा दिया है। शुरुआती सौ दिनों के भीतर ही न केवल गंगा के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया बल्कि पवित्रपावनी गंगा को निर्मल बनाने के लिए 2,037 करोड़ रुपये की 'नमामि गंगे' योजना का भी ऐलान किया गया। साथ ही गंगा तथा यमुना के घाटों के संरक्षण के लिए भी 100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। पहली बार किसी सरकार ने प्राथमिकताओं में गंगा को इतना ऊपर रखा है। गंगा को निर्मल बनाने के प्रयास काफी समय से किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसके बाद भी गंगा का प्रदूषण घटने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा हमारी राष्ट्रीय एवं पवित्रतम नदी है। इसके तट पर अनेक तीर्थस्थल विराजमान हैं। गंगा घाटी में भारत की लगभग 37 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 27 नगर इसके किनारे बसे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नगर कानपुर है और दूसरा पटना है। मछलियों की लगभग 375 प्रजातियाँ गंगा में पाई जाती हैं जो मत्स्य उद्योग को सशक्त आधार प्रदान करती हैं। गंगा का आर्थिक महत्त्व देश को इसके द्वारा प्राप्त पर्यटन उद्योग से उत्पन्न आय के कारण भी है। इसके तट पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण अनेक पर्यटन स्थल स्थित हैं।

वर्तमान समय में देश के नये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने गंगा मंत्रालय का गठन किया। मंत्रालय द्वारा गंगा नदी तीन साल में साफ होगी, सात साल में व्यवस्था दुरुस्त होगी, तभी दस साल में अविरल व निर्मल गंगा की कल्पना साकार हो सकेगी। सरकार ने इसके लिए दीर्घ व अल्पावधि योजनाएँ तैयार की हैं। अल्पावधि के तहत तीन साल में गंगा में कल कारखानों का रासायनिक कचरा गिरने से रोका जायेगा जबकि दीर्घ अवधि में उसकी धारा अविरल हो जायेगी। इस स्वच्छ गंगा परियोजना का आधिकारिक नाम "एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना" या 'नमामि गंगे परियोजना' रखा गया है। यह वस्तुतः प्रधानमंत्री का ड्रीम मिशन है। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक कुछ ही माह में यह परियोजना प्रारंभ कर दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रीय प्रशासन ने कहा है कि इस परियोजना को पूरा करने में 18 वर्षों का समय लगेगा क्योंकि यह मेगा परियोजना है। यह लगभग पूरे देश को कवर करती है। भारत के पाँच राज्य उत्तराखण्ड, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार गंगा नदी के पथ में आते हैं। इसके अतिरिक्त सहायक नदियों के कारण हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के कुछ भाग भी इस परियोजना में आ जाते हैं। हरिद्वार के अलावा देश के 108 केन्द्रों पर इस मुहिम की एक साथ शुरुआत की जा चुकी है। यह परियोजना जुलाई 2014 से गतिमान है। नमामि गंगे मिशन-II को 2026 तक 22,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रमुख उपलब्धियों के कारण गंगा स्वच्छ एवं निर्मल बनाने की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया के सबसे लम्बे रिवर क्रूज "गंगा विलास" को 13 जनवरी को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह क्रूज वाराणसी की गंगा नदी से डिब्रूगढ़ की ब्रह्मपुत्र नदी तक जायेगा। यात्रा में भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों की 27 नदी प्रणालियों के द्वारा यह क्रूज 3,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। इस क्रूज से यात्रा करने वालों को कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का भी अनुभव मिलेगा। इसकी 51 दिन की यात्रा में विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी-घाटों के दर्शन होंगे। गंगा विलास 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है जो 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। यात्रियों को बिहार के पटना,

झारखंड के साहिबगंज, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, बांग्लादेश के ढाका और असम के गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों का नजारा भी देखने को मिलता है। इसमें तीन डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सुइट हैं। यह प्रदूषणमुक्त प्रणाली और शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। एमवी गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक थे। डिब्रूगढ़ में 01 मार्च 2023 को सर्वप्रथम इसका आगमन हुआ था। 3200 किलोमीटर की यात्रा इस क्रूज ने 51 दिनों में पूरी की।

सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और संस्कारों में गंगा की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए अब तक 123 घाटों और 36 श्मशान घाटों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि हरिद्वार के चंडीघाट में गंगा अवलोकन संग्रहालय स्थापित किया गया है। नदी के घाटों और नदी की सतह पर तैरने वाले ठोस कचरे के संग्रह के लिए नदी की सतह की सफाई और इसके निपटान का कार्य चल रहा है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत, विभिन्न जैव-विविधता संरक्षण परियोजनाएं जैसे जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प परियोजना, गंगा नदी में मछली और मत्स्य संरक्षण परियोजना एवं गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त देहरादून, नरौरा, इलाहाबाद, वाराणसी और बैरकपुर में 5 जैव-विविधता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

NMCG के अधिकारियों ने नियमित रूप से सीवेज उपचार संयंत्रों (STP) का निरीक्षण किया और जहां भी आवश्यक था अधिकारियों को निर्देश जारी किए। NMCG ने नदी तटों पर खनन गतिविधियों को विनियमित करने, अतिक्रमण पर रोक लगाने और मूर्तियों के विसर्जन जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के निर्देश भी जारी किए। NMCG ने उपग्रह चित्र, सुदूर संवेदी और भू-स्थानिक समाधान जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया जिससे गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषकों की वास्तविक समय निगरानी की सुविधा मिली। नए सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे को अभिकल्पित करने के लिए वैज्ञानिक पूर्वानुमान मॉडल का प्रयोग किया गया।

नदी की सफाई में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, गंगा के किनारे के शहरों, कस्बों और गांवों में 'गंगा प्रहरियों' नामक एक नव-स्थापित सामुदायिक बल के माध्यम से नियमित रूप से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इनके माध्यम से, सरकार 'जल चेतना' को 'जन चेतना' में बदल कर इसे 'जल आन्दोलन' में बदलना चाहती है। रैलियों, अभियानों, प्रदर्शनों, श्रमदान, स्वच्छता अभियान, प्रतियोगिताओं, वृक्षारोपण अभियान और संसाधन सामग्री के विकास और वितरण के माध्यम से विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। व्यापक प्रचार के लिए टीवी/रेडियो, प्रिंट मीडिया विज्ञापन जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। औद्योगिक प्रवाह निगरानी के माध्यम से 800 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (CPI) में से 640 में वास्तविक समय प्रवाह प्रबोधन केन्द्र (EMS) स्थापित किए गए हैं। अब तक 135 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं और अन्य को निर्धारित मानदंडों के अनुपालन और ऑनलाइन EMS की स्थापना के लिए समय सीमा दी गई है। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए उसमें पॉलीथीन, मरे हुए जीव-जन्तुओं आदि को फेंकने पर रोक लगाई गई, तभी गंगा स्वच्छ एवं निर्मल है। हमें नैतिक तथा पर्यावरणीय मूल्यों का सहारा लेते हुए गंगा नदी में नालों और सीवरों के गन्दे पानी को मिलने से रोकना, गंगा प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल बचत तकनीकी विधियों के विकास के अन्तर्गत वर्षा जल के संरक्षण, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। गंगा के घाटों पर जगह-जगह प्रतिदिन किए जाने वाले कर्मकाण्ड, पूजा तथा स्नान के कारण जलधारा सबसे अधिक प्रदूषित होती है। इसके लिए मुख्य धारा में से एक पृथक धारा निकालकर इन धार्मिक अनुष्ठानों हेतु अलग व्यवस्था की जा सकती है और तत्पश्चात् इस पानी को मुख्य धारा से अलग रखकर सिंचाई में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन गंगा का एक और पहलू भी है, जिसे हम सब ने मिलकर रचा है। हम सबने इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार कर दिया है। अब ये हम सब की गंदगी, घरों से निकला कूड़ा, कारखानों से निकल रहे जहरीले अवशिष्ट को ढोने वाली नदी में तब्दील हो चुकी है। इस पानी में खुद गंगा का श्वास लेना मुश्किल हो चुका है। विकास के नाम पर इसके अविरल प्रवाह को बाँधा जाने लगा। हलांकि मौजूदा सरकार की हालिया पहल को देखें तो लगता है कि गंगा को लेकर अब केवल सरकारी खानापूर्ति या हवा-हवाई बातें नहीं हो रही हैं। बल्कि वास्तविक धरातल पर भी एक मजबूत संरचना तैयार होती हुई एवं क्रियान्वित होती हुई महसूस होने लगी है। सरकार पावन सलिला को अविरल बनाने के लिए एड़ी-चोटी से लग गई है। हम सभी चाहते हैं कि गंगा नैसर्गिक रूप में सदा बेहतर नीर बनकर प्रवाहमान रहे। इसके लिए सर्वप्रथम तो गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाना चाहिए और जिस तरह से हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार गंगा को भी सम्मान एवं सुरक्षा मिलनी चाहिए। गंगा की पवित्रता और अविरलता के सातत्य के लिए विकास के नाम पर हो रहे विनाश को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 'नमामि गंगे' कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 231 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। इनके अन्तर्गत गंगा घाटों के निर्माण और श्मशानों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ वृक्षारोपण भी सम्मिलित है। सरकार ने इस कार्यक्रम में गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को शामिल करने की नीति बनाई ताकि बेहतर और दूरगामी परिणाम सामने आ सकें।

केन्द्र की इस परियोजना को सशक्त ढंग से लागू करने हेतु गंगा इको टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गंगा का प्रदूषण आज भी एक बड़ा मुद्दा है केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अनेकानेक प्रयासों के बावजूद गंगा अविरल और निर्मल नहीं हो सकी है। घाटों पर फैली गन्दगी की सफाई न होने और पॉलीथीन का प्रयोग जारी रहने से स्थिति खराब हो रही है। सरकार द्वारा जन-जागरण अभियान के माध्यम से देश के कोने-कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पॉलीथीन का प्रयोग न करने और गंगा रक्षा हेतु उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध कराने का कार्य हर वर्ष निरन्तर किया जा रहा है। इनमें गंगा की वर्तमान दशा, उसमें गिरने वाले नालों की संख्या, प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। हमारे कुलपति महोदय का गंगा और गाँव से लगाव इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। केन्द्र सरकार ने इस सम्बंध में जागरूकता लाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है। माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के कर कमलों द्वारा जारी 'भुवन गंगा' मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल की शुरुआत का उद्देश्य इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी बनाना और उस पर नजर रखना है। निर्मल गंगा अभियान की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि गंगा प्रवाह को किस प्रकार सुनियंत्रित किया जाए ताकि वर्ष भर गंगा में पानी के अविरल बहाव का एक न्यूनतम स्तर निश्चित किया जा सके। इसकी शुरुआत हिमालय में गंगा की सहायक नदियों और गंगा की मुख्य धारा पर कंक्रीट के बाँध बनाकर की जा सकती है। हिमालय में गंगा के बहाव के मार्ग में इतना ढलान है कि लगभग हर तीस किलोमीटर पर बाँध निर्मित कर झीलें बनाई जा सकती हैं। इससे पानी का बहाव तो नियंत्रित होगा ही, बल्कि वर्ष भर गंगा की अविरलता भी सुनिश्चित हो सकेगी। गंगा सफाई अभियान में दूसरी बड़ी चुनौती गंगा को मैदानी क्षेत्रों में नियंत्रित करने से सम्बन्धित है। हरिद्वार से निकलते ही गंगा कई मील चौड़ी जलधारा में बदल जाती है। तटों को पार करता हुआ गंगा का पानी प्रतिवर्ष एक बहुत विशाल क्षेत्र में तबाही मचाता हुआ समुद्र में जा मिलता है। इन तटों को मजबूत बनाकर मैदानी क्षेत्रों में गंगा पर प्रत्येक तीस किलोमीटर पर एक कम ऊँचाई वाला मिट्टी का बाँध बनाया जा सकता है। इस पानी से गंगा के दोनों ओर कम से कम पचास किलोमीटर के क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई का प्रबन्ध कर सकते हैं। निर्मल गंगा हेतु 'नमामि गंगे' परियोजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी बजट की धनराशि पिछले 30 साल में खर्च की गई धनराशि से चार गुना ज्यादा है। निर्मल गंगा अभियान का कार्य सरल नहीं है इसके लिए हर स्तर पर समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत अभियन्ताओं, धार्मिक संगठनों से जुड़े धर्मगुरुओं, प्रबुद्ध सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधिगण, यातायात विशेषज्ञ, नहर विभाग के अभियन्ताओं, जल परियोजना से सम्बद्ध अभियन्ताओं, योजना विभाग के विशेषज्ञों और जन प्रतिनिधियों सभी को आपसी तालमेल से कार्य करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सभी सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग की भी स्थापना होनी चाहिए जो स्वतन्त्र फैसले लेने में सक्षम हो। स्पष्ट है कि व्यापक कानूनों के निर्माण और उनके सख्ती से पालन द्वारा ही यह सब संभव हो सकता है। नमामि गंगे के तहत जलवाही स्तर की वृद्धि करने, कटाव कम करने तथा नदी के परिस्थितिकी तन्त्र की स्थिति में सुधार हेतु 30,000 हेक्टेयर भूमि पर वन लगाए जाने हैं। गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार ने 'निर्मल गंगा सहभागिता' की पहल की है। इसके अन्तर्गत सरकार गंगा किनारे की 118 नगर पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाएगी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जल ही नहीं अपितु भारत की मानवीय चेतना को भी प्रवाहित करती है। इस नदी की घाटी में ही रामायण और महाभारतकाल युग का उद्भव और विलय हुआ। प्राचीन मगध महाजनपद का उद्भव भी गंगा घाटी में ही हुआ, जहाँ से गणराज्यों की परंपरा विश्व में प्रथम बार प्रारंभ हुई। यहीं भारत का स्वर्णयुग विकसित हुआ जब मौर्य और गुप्तवंशीय राजाओं ने यहाँ शासन किया था। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और अनेक पुराणों में गंगा को पुण्यवेला, पाप-नाशिनी, मोक्षदायक, सरिता एवं महानदी कहा गया है। संस्कृत और हिन्दी साहित्य के अनेक कवियों ने गंगा की महिमा का सुन्दर शब्दों में गायन किया है। हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता, अखण्डता व गरिमा की प्रतीक गंगा नदी की निर्मलता का सपना भारत और भारत से बाहर के लोगों का भी सपना रहा है। गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण गंगा जल में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके जल को शुद्ध रखने की अमोघ क्षमता है। मैदानों में गंगा प्रदूषण की स्थिति कितनी भी विकट हो पहाड़ों से निकलती गंगा सदा शुद्ध शीतल रही है। गंगा का यह निर्मल जल मूलतः जीवनदायक भौतिक संसाधन है। चाहे हम गंगा को पतित-पावनी माँ के रूप में स्वीकार कर उसके संरक्षण और निर्मलता की रक्षा में गौरव का अनुभव करें, चाहे अच्छे नागरिकों के रूप में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इसे बहते पानी का स्रोत मानकर इसकी निर्मलता और स्वच्छता के सातत्य हेतु मिलकर प्रयास करें— मार्ग कोई भी चुनें, सच्ची प्रतिबद्धता से ही आज हमारा कल्याण संभव है। कहा भी गया है—

“मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।”

गंगा को निर्मल बनाने के लिए वास्तव में आज फिर भगीरथ प्रयत्न की आवश्यकता है। कहना न होगा कि सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसका जितना धार्मिक महत्त्व है उतना ही आर्थिक और सांस्कृतिक महत्त्व भी है। देश के लाखों लोगों की गंगा के प्रति श्रद्धा है और इसे गंगा स्वच्छता हेतु एक आन्दोलन में बदलने की जरूरत है।